(c) *Prima facie* there are no indications that the fire was caused by extremists.

REQUEST TO RESCIND NEWSPRINT CONTROL ORDER, 1992

@*315. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the President of Indian Newspaper Society recently urged Government to rescind the Newsprint Control Order, 1992 and allow the functioning of newspaper industry in a liberalised environment;

(b) if so, what steps have been taken by Government to rescind the Newsprint Control Order, 1992; and

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) to (c) Yes, Sir. The Indian Newspaper Society have requested to rescind the Newsprint Control order, 1962. However, the request has financial implications for the domestic newsprint industry and is also dependant on the decisions in the Union Budget, 1994-95.

उत्तर प्रदेश स्थित विकास केन्द्र

316. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उत्तर प्रदेश स्थित विभिन्न औद्योगिक विकास केन्द्रों को क्या-क्या आधारभूत सुविधायें प्रदान की हैं;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के ऐसे केन्द्रों में निष्पादित किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त विकास केन्द्र अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्य को निष्पादित नहीं कर पा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री, उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) से (घ) : विकास केन्द्र योजना, 1988 के अधीन केन्द्रों के विकास के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धन दिया जाता है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास केन्द्रों के लिए अब तक 3.5 करोड़ रु. जारी किए हैं और 8 में से 6 परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया है जो राज्य सरकार द्वारा किया जाना है राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लिए जाने के बाद ही इस कार्य में तेजी आयेगी। योजना को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाना है। विकास केन्द्रों को बिजली, पानी, दूरसंचार, सड़क और बैंक जैसी मूल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए योजना

317. **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ दिन पूर्व प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की गोष्ठी में [illegible]

@ Previously starred Question 255, transferred from 20th December, 1993.